

संख्या:- 452 /XXXVI(2)/25/E-File No. 72730

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2025

विषय-मा0 उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-181/XXVI(2)2008-120-एक(1)/04 दिनांक 06.10.2008 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य किया गया है। शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित/वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. स.	पदनाम	वर्तमान दर प्रतिमाह	संशोधित दर प्रतिमाह
1.	विशेष आशुलिपिक/कार्यपालक सहायक जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा चयन के उपरान्त की गयी हो, को विशेष भत्ता।	रु. 200/-	रु. 540/-
2.	आशुलिपिक को यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता/विशेष भत्ता:- (I) ऐसे आशुलिपिक जो तहसील/जिला मुख्यालय में कार्यरत हैं, (II) जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में कार्यरत वैयक्तिक सहायक।	रु. 100/- रु. 200/-	रु. 270/- रु. 540/-

2- उक्तवत भत्तें निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होंगे:-

- सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को राजकीय वाहन आवंटित होने अथवा सम्बन्धित यात्राओं हेतु राजकीय वाहन का उपयोग किये जाने की दशा में उक्तवत भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी अवकाश अवधि में विशेष भत्ता/यात्रा

- भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. जिन अल्प दूरी की यात्राओं के लिए विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य किया गया हो उन यात्राओं के लिए साधारण यात्रा भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 4. शासनादेश संख्या-181/XXVI(2)2008-120-एक(1)/04 दिनांक 06.10.2008 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. उक्तवत अनुमन्य भत्तों को आहरित करने से पूर्व संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त भत्तों का दावा उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुरूप है।
 6. उक्त दरें दिनांक 01.04.2025 से लागू होंगी।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय, 03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश की सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।
- 4-यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-I/290390/2025, दिनांक 16 अप्रैल, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Pradeep Pant
Date: 17-04-2025
18:29:19

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
- 2-सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 21-04-2025
11:34:10

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।